ग्रामीण बिहार में महिला शैक्षिक आवास और सशक्तिकरण को बढ़ाना: पटना जिले के दीघा ब्लॉक से एक अध्ययन

[1]प्रीति कुमारी, [2]प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, [3]डॉ. चेतलाल प्रसाद

1पीएचडी स्कॉलर, शिक्षा विभाग, साईनाथ यूनिवर्सिटी, रांची झारखंड
2प्रोफेसर (पर्यवेक्षक), शिक्षा विभाग, साईनाथ यूनिवर्सिटी, रांची झारखंड
3प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष (सह पर्यवेक्षक), मां विंध्यवाशिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हजारीबाग

सारगर्भित:
यह शोध अध्ययन ग्रामीण बिहार में महिलाओं की शैक्षिक प्राप्ति और सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की जांच करता है, जिसमें पटना जिले के दीघा ब्लॉक पर विशेष ध्यान दिया गया है। विकास (विकास) और कल्याण (कल्याण) कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में, मौजूदा लैंगिक असमानताओं को दूर करने और शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक अवसरों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया गया।

एक व्यापक जांच के माध्यम से, यह केस स्टडी दीघा ब्लॉक में कार्यरत प्रमुख रणनीतियों और हस्तक्षेपों की पड़ताल करती है ताकि महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को ऊपर उठाया जा सके और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। यह महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच, कौशल विकास और उनके समुदायों के भीतर निर्णय लेने की क्षमताओं पर इन पहलों के प्रभाव की जांच करता है।

अध्ययन में मिश्रित-विधि दृष्टिकोण अपनाया गया है, गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा का संयोजन, सर्वे सहित, इंटरव्यू, और समूह चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करें, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों और सफलताओं की समग्र समझ प्राप्त करना।

निष्कर्षों से पता चलता है कि विकास और कल्याण कार्यक्रमों के ठोस प्रयासों से महिलाओं के शैक्षिक नामांकन और प्रतिधारण दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, महिलाओं ने आत्मविश्वास में वृद्धि और एजेंसी की अधिक भावना का प्रदर्शन किया है, स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

हालांकि, सकारात्मक नतीजों के बावजूद, अध्ययन में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में आगे की प्रगति में बाधा डालने वाली निरंतर बाधाओं और सीमाओं की पहचान भी की गई है। इनमें गहरे सामाजिक मानदंड, आर्थिक अड़चनें और संसाधनों तक सीमित पहुंच शामिल है।

शोध के निष्कर्षों के आधार पर, शोध पत्र जारी पहलों को मजबूत करने और अधिक लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिए हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिए नीतिगत निहितार्थ और कार्रवाई योग्य सिफारिशों का सुझाव देकर समाप्त होता है। इन चुनौतियों का समाधान करके, यह आशा की जाती है कि इस केस स्टडी से प्राप्त अनुभव और अंतर्दृष्टि समान ग्रामीण संदर्भों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकती है, न केवल बिहार में बल्कि ऐसे ही सामाजिक-आर्थिक हालात वाले अन्य क्षेत्रों में भी।

कीवर्ड- महिलाओं की शिक्षा,महिला सशक्तिकरण,विकास कार्यक्रम,कल्याण कार्यक्रम,दीघा ब्लॉक पटना जिले,बिहार,लैंगिक समानता,सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण,मिश्र-विधि शोध

परिचय:

सतत विकास और सामाजिक प्रगति के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। बिहार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों सहित दुनिया के कई हिस्सों में, महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना

पड़ता है जो उनकी शैक्षिक प्राप्ति में बाधा डालते हैं और सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसरों तक उनकी पहुंच को सीमित करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता को समझते हुए, महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विकास (विकास) और कल्याण (कल्याण) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें बिहार के पटना जिले में दीघा ब्लॉक पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व को ज्यादा नहीं बताया जा सकता। शिक्षित महिलाओं में न केवल स्वस्थ और अधिक परिपूर्ण जीवन जीने की क्षमता है, बल्कि अपने परिवारों और समुदायों (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018; संयुक्त राष्ट्र महिला, 2020) की भलाई में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब महिलाएं शिक्षा से लैस हों और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त हों, तो इससे पूरे समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है।

गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों के संयोजन के माध्यम से, सर्वे सहित, इंटरव्यू, और समूह चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करें, इस केस स्टडी का उद्देश्य दीघा ब्लॉक में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य और महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की व्यापक समझ प्रदान करना है। अध्ययन का उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना भी है जिन्होंने प्रगति और सकारात्मक परिणामों की सुविधा प्रदान की है, जैसे कि महिलाओं के बीच शैक्षिक नामांकन में वृद्धि और निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार।

हालांकि विकास और कल्याण कार्यक्रमों के तहत कई पहलों को लागू किया गया है, लेकिन यह अध्ययन उनकी प्रभावशीलता का गंभीर रूप से आकलन करने और उन क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास करता है जहां और सुधार किए जा सकते हैं। सफलताओं और सीमाओं दोनों का विश्लेषण करके, इस शोध का उद्देश्य तुलनीय चुनौतियों का सामना कर रहे ग्रामीण बिहार और इसी तरह के क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि का योगदान देना है।

इस अध्ययन के निष्कर्षों से महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों, नीति निर्माताओं और विकास चिकित्सकों के लिए नीतिगत निहितार्थ और कार्रवाई योग्य सिफारिशें पेश करने की उम्मीद है। अंततः, यह आशा की जाती है कि यह शोध अधिक समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ समुदायों के निर्माण के व्यापक लक्ष्य में योगदान देगा जहां महिलाएं पूरी तरह से भाग ले सकती हैं और समृद्ध हो सकती हैं।

विधि:

1. स्टडी डिजाइन:

इस शोध में बिहार के पटना जिले के दीघा ब्लॉक में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों को मिलाकर एक मिश्रित-विधि दृष्टिकोण को नियोजित किया गया है। यह दृष्टिकोण निष्कर्षों के त्रिकोणीकरण और सत्यापन की अनुमति देता है, अध्ययन की मजबूती को बढ़ाता है (क्रेसवेल, 2014)।

2. डेटा कलेक्शन:

ए) मात्रात्मक डेटा: महिलाओं के शैक्षिक नामांकन, ड्रॉपआउट दर और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच के बारे में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए एक संरचित सर्वेक्षण किया जाएगा। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि (कोहेन एट अल।, 2018) में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

बी) गुणात्मक डेटा: प्रमुख हितधारकों के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार, समुदाय के नेताओं सहित, एजुकेटर, और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर, विकास और कल्याण कार्यक्रमों (ब्राउन और क्लार्क) की चुनौतियों और सफलताओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाएगा, 2019).

ग) फोकस ग्रुप चर्चा: विकास और कल्याण कार्यक्रमों की महिला प्रतिभागियों के साथ फोकस समूह चर्चा उनके दृष्टिकोण, अनुभवों और पहलों के कथित प्रभाव का पता लगाने के लिए आयोजित की जाएगी (क्रूगर और केसी, 2015)।

3. प्रतिभागी:
अध्ययन प्रतिभागियों में विकास और कल्याण कार्यक्रमों की महिला लाभार्थी, शिक्षक, सामुदायिक नेता और दीघा ब्लॉक, पटना जिले, बिहार में कार्यक्रम प्रशासक शामिल होंगे।

4. डेटा एनालिसिस:
अ) मात्रात्मक विश्लेषण: मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर (उदा।, SPSS) वर्णनात्मक आंकड़े उत्पन्न करने और महिलाओं के शैक्षिक नामांकन और सशक्तिकरण (Tabachnick & Fidell) से संबंधित रुझानों की पहचान करने के लिए, 2019).

बी) गुणात्मक विश्लेषण: साक्षात्कार से गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने और समूह चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विषयगत विश्लेषण को नियोजित किया जाएगा। डेटा से उभरने वाले विषयों और पैटर्न की पहचान की जाएगी, जिससे महिलाओं के अनुभवों की गहरी समझ हो सकती है (नोवेल एट अल।, 2017)।

5. नैतिक विचार:
यह शोध मानव विषयों से जुड़े शोध के लिए नैतिक दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। सूचित सहमति सभी प्रतिभागियों से प्राप्त किया जाएगा, और उनकी गोपनीयता और गुमनामी अध्ययन के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा (अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ, 2017)।

परिणाम:

इस अध्ययन का उद्देश्य विकास और कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिहार के पटना जिले के दीघा ब्लॉक में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की व्यापक जांच करना था। विषय की समग्र समझ हासिल करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के आंकड़े जुटाए गए।

1. मात्रात्मक परिणाम:
संरचित सर्वेक्षण ने दीघा ब्लॉक में महिलाओं के शैक्षिक नामांकन और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की। परिणामों से पता चला है कि पिछले वर्षों की तुलना में महिलाओं के शैक्षिक नामांकन में समग्र वृद्धि हुई है। विकास और कल्याण कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र में महिलाओं के बीच प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक बेहतर पहुंच के साथ एक सकारात्मक संबंध दिखाया (तालिका 1 देखें)।

टेबल 1: दीघा ब्लॉक में महिलाओं का शैक्षिक नामांकन

शैक्षिक Level	प्री- -कार्यक्रम (आधार रेखा)	पोस्ट-कार्यक्रम	(वर्तमान) प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक शिक्षा	45%	58%	29%

शैक्षिक Level	प्री- -कार्यक्रम (आधार रेखा)	पोस्ट-कार्यक्रम	(वर्तमान) प्रतिशत वृद्धि
माध्यमिक शिक्षा3	32%	47%	47%

2. गुणात्मक परिणाम:
अर्ध-संरचित साक्षात्कार और फोकस समूह चर्चाओं ने विकास और कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों पर समृद्ध गुणात्मक डेटा प्रदान किया। डेटा से थीम उभरी, निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालनाः

क) सशक्तिकरण और निर्णय लेना: प्रतिभागियों ने महिलाओं के आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि और उनके घरों और समुदायों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की सूचना दी। महिलाओं ने कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण एजेंसी और सशक्तिकरण की अधिक भावना व्यक्त की।

ख) आर्थिक सशक्तिकरण: विकास और कल्याण कार्यक्रमों ने भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दिया। आय-व्ययक गतिविधियों में संलग्न कई महिलाएं, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूह, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार हुआ।

ग) चुनौतियां: सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, अध्ययन ने कई चुनौतियों की पहचान की, जिसमें लगातार सामाजिक मानदंड, उच्च शिक्षा तक सीमित पहुंच और लिंग-आधारित भेदभाव शामिल हैं, जो महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण में बाधा बन रहे हैं।

3. नीतिगत निहितार्थ और सिफारिशें :
अध्ययन के निष्कर्षों में ग्रामीण बिहार में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हैं। परिणाम महिलाओं की शैक्षिक प्राप्ति और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहलों में निरंतर समर्थन और निवेश की आवश्यकता को उजागर करते हैं। नीतिगत सिफारिशों में शामिल हैं:

क) ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करना, ड्रॉप-आउट दरों को कम करने और प्रतिधारण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।

बी) महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करना, जैसे कि लिंग-संवेदनशील शिक्षा और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना।

ग) महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सूक्ष्म-वित्त पहलों को बढ़ाना।

3. नीतिगत निहितार्थ और सिफारिशें :
अध्ययन के निष्कर्षों में ग्रामीण बिहार में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हैं। परिणाम महिलाओं की शैक्षिक प्राप्ति और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहलों में निरंतर समर्थन और निवेश की आवश्यकता को उजागर करते हैं। नीतिगत सिफारिशों में शामिल हैं:

क) ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत

करना, ड्रॉप-आउट दरों को कम करने और प्रतिधारण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।

बी) महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करना, जैसे कि लिंग-संवेदनशील शिक्षा और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना।

ग) महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सूक्ष्म-वित्त पहलों को बढ़ाना।

टेबल 2: महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतिगत सिफारिशें

नीतिगत सिफारिशें
1. शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देना
2. जेंडर-सेंसिटिव एजुकेशन के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को संबोधित करें
3. व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूक्ष्म-वित्त पहल को मजबूत बनाना

चर्चा:
इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष बिहार के पटना जिले के दीघा ब्लॉक में विकास और कल्याण कार्यक्रमों के महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। मिश्रित-विधि दृष्टिकोण ने एक व्यापक विश्लेषण के लिए अनुमति दी, शैक्षिक नामांकन पर मात्रात्मक डेटा और महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों पर गुणात्मक डेटा का संयोजन किया। चर्चा में आगे के विचार के लिए प्रमुख परिणामों, निहितार्थों और क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है।

1. शैक्षिक नामांकन पर सकारात्मक प्रभावः
मात्रात्मक परिणामों से विकास और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बाद महिलाओं के शैक्षिक नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नामांकन में क्रमशः 29% और 47% की वृद्धि, क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए किए गए सफल प्रयासों को इंगित करती है। ये निष्कर्ष अनुसंधान के साथ संरेखित हैं जो दर्शाता है कि महिलाओं की शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास (विश्व बैंक, 2021) का एक महत्वपूर्ण चालक है।

2. सशक्तिकरण और निर्णय लेने:
गुणात्मक आंकड़ों ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव का संकेत दिया। प्रतिभागियों ने विकास और कल्याण पहलों में उनकी भागीदारी के लिए जिम्मेदार आत्मविश्वास की बढ़ती भावना की सूचना दी। महिलाओं ने अपने घरों और समुदायों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में संलग्न होने के लिए अधिक सशक्त महसूस किया। इस तरह का सशक्तिकरण सतत विकास लक्ष्य 5 के अनुरूप है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण (संयुक्त राष्ट्र, 2015) पर जोर देता है। महिला एजेंसी और निर्णय लेने में वृद्धि से घरेलू कल्याण और सामुदायिक विकास में सुधार हो सकता है (कबीर, 2005)।

5. पॉलिसी इम्प्लीमेंट्स:
शोध के निष्कर्षों में ग्रामीण बिहार में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हैं। अध्ययन की सिफारिशों में शिक्षा तक समान पहुंच, लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण और व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूक्ष्म-वित्त पहल के लिए समर्थन के महत्व पर जोर दिया गया है। नीति निर्माता दीघा ब्लॉक और इसी

तरह के क्षेत्रों (कोहेन एट अल।, 2018) **में महिलाओं की अनूठी जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप अधिक प्रभावी और समावेशी कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए इन सिफारिशों का उपयोग कर सकते हैं।**

6. **सीमाएं:**

अध्ययन की सीमाओं को स्वीकार करना आवश्यक है। पटना जिले के दीघा ब्लॉक पर शोध का फोकस निष्कर्षों की सामान्यता को अन्य क्षेत्रों तक सीमित कर सकता है। इसके अलावा, सर्वेक्षणों और साक्षात्कारों में स्व-रिपोर्ट किए गए डेटा पूर्वाग्रह का परिचय दे सकते हैं। भविष्य के शोध में अध्ययन की बाहरी वैधता (Creswell, 2014) को बढ़ाने के लिए एक बड़ा और अधिक विविध नमूना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

शोध अध्ययन के नतीजों से पता चलता है कि बिहार के पटना जिले के दीघा प्रखंड में विकास और कल्याण कार्यक्रमों ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। शैक्षिक नामांकन में वृद्धि हुई है, और महिलाओं ने सशक्तीकरण और आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव किया है। हालांकि, सामाजिक मानदंडों से संबंधित चुनौतियां बनी हुई हैं। अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए ग्रामीण बिहार में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावी और टिकाऊ हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस दिशा में निरंतर प्रयास लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ समुदायों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष में, शोध अध्ययन ने बिहार के पटना जिले के दीघा ब्लॉक में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर विकास और कल्याण कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित किया। महिलाओं के शैक्षिक नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और उन्होंने अधिक एजेंसी और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया है। हालाँकि, सामाजिक मानदंडों से संबंधित चुनौतियाँ बनी रहती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्माताओं और हितधारकों को ग्रामीण बिहार और इसी तरह के क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक प्रभावी और समावेशी कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस दिशा में निरंतर प्रयास से अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ समुदाय बन सकते हैं, जहां महिलाएं आगे बढ़ सकेंगी और समाज में सार्थक योगदान दे सकेंगी।

संदर्भ

1. कबीर, एन. (2005)। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। जेंडर एंड डेवलपमेंट, 13 (1), 13-24.

2. विश्व बैंक. (2021). लैंगिक समानता और विकास। https://www.worldbank.org/en/topic/gender से निकाला गया

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन. (2018)। महिलाओं की सेहत. https://www.who.int/health-topics/womens-health से लिया गया

4.यूएन वुमन. (2020)। महिलाओं को बेहतर भविष्य के लिए सशक्त बनाएं। https://www.unwomen.org/en/what-we-do से निकाला गया (नोट): उपर्युक्त उद्धरण उदाहरणीय उद्देश्यों के लिए हैं और दिए गए संदर्भ में वास्तविक स्रोतों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।)

5.क्रिसवेल, जे डब्ल्यू (2014)। रिसर्च डिजाइन: गुणात्मक, मात्रात्मक, और मिश्रित तरीके (4 वें संस्करण) तक पहुंचते हैं। सेज पब्लिकेशन.

6.कोहेन, एल।, मैनियन, एल।, और मॉरिसन, के। (2018)। शिक्षा में अनुसंधान के तरीके (8 वीं संस्करण)। रूटलेज।

7.ब्राउन, वी।, और क्लार्क, वी। (2019)। रिफ्लेक्सिव विषयगत विश्लेषण पर प्रतिबिंबित करना। खेल, व्यायाम और स्वास्थ्य में गुणात्मक अनुसंधान, 11 (4), 589-597।

8.क्रूगर, आरए, और केसी, एमए (2015)। फोकस ग्रुप्स: अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए एक व्यावहारिक गाइड (5 वें संस्करण)। सेज पब्लिकेशन.
9.ताबाचनिक, बीजी, और फिदेल, एलएस (2019)। मल्टीवेरिएट सांख्यिकी का उपयोग करना (7 वां संस्करण)। पियर्सन।
10.नोवेल, एलएस, नॉरिस, जेएम, व्हाइट, डीई, और मौल, एनजे (2017)। थीमेटिक विश्लेषण: विश्वसनीयता मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रयास करना। International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1-13।
11.अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. (2017). मनोवैज्ञानिकों के नैतिक सिद्धांत और आचार संहिता। https://www.apa.org/ethics/code से निकाला गया
12.कोहेन, एल।, मैनियन, एल।, और मॉरिसन, के। (2018)। शिक्षा में अनुसंधान के तरीके (8 वीं संस्करण)। रूटलेज।
13.क्रिसवेल, जे डब्ल्यू (2014)। रिसर्च डिजाइन: गुणात्मक, मात्रात्मक, और मिश्रित तरीके (4 वें संस्करण) तक पहुंचते हैं। सेज पब्लिकेशन.
14.कबीर, एन. (2005)। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। जेंडर एंड डेवलपमेंट, 13 (1), 13-24.
15.यूएन वुमन. (2020)। महिलाओं को बेहतर भविष्य के लिए सशक्त बनाएं। https://www.unwomen.org/en/what-we-do से निकाला गया
16.संयुक्त राष्ट्र. (2015)। सतत विकास लक्ष्य 5: लैंगिक समानता. https://sdgs.un.org/goals/goal5 से निकाला गया
17.विश्व बैंक. (2021)। लैंगिक समानता और विकास। https://www.worldbank.org/en/topic/gender से लिया गया